दिल्ली मेट्रो ने रचा इतिहास, इस स्टेशन को मिला खास पुरस्कार; राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के पिंक लाइन के ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत मेट्रो स्टेशनों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन पर ऊर्जा-दक्षता में अनुकरणीय प्रयासों के लिए विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के कर-कमलों से डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने देश भर की विभिन्न मेट्रो रेल प्रणालियों से प्राप्त आवेदनों के बहुत व्यापक मूल्यांकन के बाद इस स्टेशन का चयन किया।

बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 62 ● नई दिल्ली ● सोमवार 15 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली-एनसीआर में सांसों का आपातकाल

नई दिल्ली ।

राजधानी में हवा की धीमी गति और खराब मौसम के चलते रविवार को हवा इस साल की सबसे खराब श्रेणी में पहुंच गई। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से हुई और आसमान में स्मॉग की मोटी चादर के चलते दृश्यता भी कम रही। सांस लेने में हो रही दुश्वारी के बीच लोग मास्क पहने नजर आए। लोगों को आंख में जलन की दिक्कत भी हुई। वहीं, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार, रविवार सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 462 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सुबह सात बजे को आंकड़ों के अनुसार, राजधानी दिल्ली के अलीपुर में एक्यूआई 439, आनंद विहार में एक्यूआई 491, अशोक विहार में 493, आया नगर में 447, बवाना में 495, बुराड़ी में 473, चांदनी चौक इलाके में 462 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं, डीटीयू में 493, द्वारका सेक्टर 8 में 454, आईजीआई एयरपोर्ट टी3 इलाके में 411, आईटीओ में 482, जहांगीरपुरी में 495, लोधी रोड 401, मुंडका 486, नजफगढ़ में 411, पंजाबी बाग में 475, रोहिणी 499, विवेक विहार 495, सोनिया विहार 483, आरकेपुरम 472, वजीरपुर में 493 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में भी एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, वसुंधरा में 482 एक्यूआई दर्ज किया गया है। संजय नगर में 419 और इंदिरापुरम में एक्यूआई 476 दर्ज किया। नोएडा में भी कई इलाकों में 400 से ज्यादा एक्यूआई पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सेक्टर 125 में 456, सेक्टर 1 इलाके में 488 और सेक्टर 62 इलाके में 432, सेक्टर 116 इलाके में 499 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

गुरुग्राम में इतना दर्ज किया गया एक्यूआई

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गुरुग्राम के एनआईएसई ग्वाल पहाड़ी में 406 एक्यूआई दर्ज किया गया है। टेरी ग्राम में 343, विकास सदन में 293 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

फरीदाबाद का एक्यूआई

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, फरीदाबाद के सेक्टर 30 में एक्यूआई 108, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन में 183 और सेक्टर 11 में 369 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार शाम ग्रेप 4 लागू कर दिया। शनिवार सुबह ग्रेप तीन पाबंदियों की घोषणा की गई थी। इसी के साथ अब दिल्ली में ग्रेप एक दो, तीन और चार की पाबंदियां लागू होंगी। दरअसल, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत तेजी से खराब हो रही है, जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की समिति ने तत्काल प्रभाव से सबसे सख्त पाबंदियां ग्रेप 4 लागू करने का फैसला किया है। धीमी हवा, स्थिर वातावरण और खराब मौसम की वजह से प्रदूषक हवा में फैल नहीं पाए, जिससे प्रदूषण बढ़ता गया। इसके साथ ही एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रदूषण को और बढ़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त निवारक कदम उठाएं। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीएक्यूएम ने लोगों से ग्रेप के सिटीजन चार्टर का पालन करने की अपील की है।

स्टेज-1 और 2 के अलावा अतिरिक्त सलाह में छोटी दूरी के लिए पैदल व साइकिल चलाना, सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, वर्क फ्रॉम होम, कोयला-लकड़ी से गर्माहट न लेना, सुरक्षाकर्मियों को इलेक्ट्रिक हीटर देना और अनावश्यक यात्राएं कम करना शामिल है। फैसले में कहा गया है कि यह चरण 1, 2 और 3 के मौजूदा उपायों के अलावा लागू होगा। एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वायु गुणवत्ता को आगे बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई को तेज करें। नागरिकों से अपील है कि वे ग्रेप के नियमों का पालन करें ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने स्कूलों को लेकर अहम फैसला लिया है। ग्रैप स्टेज-4 लागू होने के बीच 9वीं कक्षा तक और 11वीं के छात्रों की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी। यानी जहां संभव होगा, वहां बच्चे स्कूल आकर पढ़ सकेंगे और साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी खुला रहेगा।

वहीं, सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी और निजी दफ्तर 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे। बाकी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम करना होगा। राजधानी की बिगड़ती हवा को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी और निजी दफ्तर 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे। बाकी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इस आदेश को तत्काल सख्ती से लागू करने का निर्देश है।

कांग्रेस की वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली में जुटी भीड़

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की वोट चोर, गद्दी छोड़ महारैली के लिए रामलीला मैदान में विभिन्न राज्यों से पार्टी कार्यकर्ता जुटे। सुबह से ही कार्यकर्ता मैदान के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिससे अच्छी-खासी भीड़ नजर आ रही है। कार्यकर्ता उत्साह के साथ नारे लगा रहे हैं और रैली स्थल पर मोहब्बत की दुकान नामक चाय की स्टॉल पर नाश्ता कर रहे हैं। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन मंच अभी लगभग खाली है। सभी की निगाहें बड़े नेताओं के इंतजार पर टिकी हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित अन्य शीर्ष नेता करीब एक से डेढ़ बजे मैदान पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली कथित वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है। दिल्ली से सभी प्रमुख नेता मौजूद हैं। इसमें पूर्व सांसद अजय माकन, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा व अन्य मौजूद हैं। हरियाणा

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार चोरी के वोटों से बन रही है।

आज देश में लाखों लोग ऐसे, जिनका अता पता ही नहीं क्योंकि उनका वोट ही कट गया। निष्पक्ष चुनाव के लिए हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में अभियान चलाएंगे। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा- देश को आजादी दिलाने और संविधान बनाने में कांग्रेस की बहुत अहम भूमिका है। लेकिन आज भाजपा ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। चुनाव आयोग की वोट चोरी से ही भाजपा की सरकार बन रही है। जिस दिन यह चोरी रुक गई, भाजपा की सरकार भी सत्ता से चली जाएगी। तब कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने की राजनीति की है। लेकिन यह अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी बार बार प्रमाण दे रहे कि वोट चोरी हो रही है, मगर चुनाव आयोग ने एक जांच तक नहीं बिठाई। अब हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। आज इस रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में पहुंचकर जो शक्ति प्रदर्शित की है, काबिलेतारीफ है। हमारी लंबी लड़ाई जारी रहेगी। न्याय लेकर रहेंगे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 77 साल पहले जब लोकतंत्र की स्थापना की गई थी तो जनता को सबसे बड़ी ताकत वोट डालने की दी थी। कांग्रेस ने इस ताकत को हमेशा बचाए रखा। लेकिन भाजपा ने वोट की ताकत को ही कमजोर कर दिया। आज इस महारैली में इतनी बड़ी संख्या में आकर कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया कि इस ताकत को वापस बचाकर रहेंगे। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि देश में लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके खिलाफ पार्टी के अभियान में पांच करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया है। लोगों ने अब ठान लिया है कि वोट चोरों को सत्ता से हटा कर ही दम लेंगे

खाना बनाने के दौरान झुग्गी में लगी आग, बेड पर खेल रहे दो मासूम झुलसे, एक की मौत... मचा कोहराम

नई दिल्ली । शाहदरा जिला के विवेक विहार इलाके में शनिवार रात खाना बनाने के दौरान एक झुग्गी में आग लग गई। हादसे में बेड पर खेल रहे दो मासूम आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। मां ने शोर मचाया तो पड़ोसी मदद को भागे। किसी तरह आग बुझाने के बाद मासूम को झुग्गी से बाहर निकाला गया। बाद में मासूम परी (4) और इसके छोटे भाई अंश (1) को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कुछ ही देर में अंश की मौत हो गई, वहीं परी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसे के समय मां खाना बनाते समय शौच के लिए गई थी। कुछ देर बाद वापस आई तो उसने देखा कि झुग्गी में आग लगी थी। पुलिस को देर रात जीटीबी अस्पताल से हादसे की सूचना मिली। खबर मिलने के बाद पुलिस ने मासूम का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा। क्राइम टीम व एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि चूल्हे के पास ही झुग्गी में बेड रखा हुआ था। खाना बनाने के दौरान चादर में आग लगी और हादसा हो गया। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि हादसा शनिवार रात करीब 10.15 बजे ई-80/118, राजीव कैंप, झिलमिल, विवेक विहार में हुआ। यहां अतुल पंडित का परिवार रहता है। इनके परिवार में पत्नी निशा के अलावा बेटी परी और बेटा अंश था। अतुल एक टेंट हाउस का मिनी टैंपो चलाते हैं। शनिवार को अतुल काम से बाहर थे। इनकी पत्नी घर में आलू उबाल रही थीं। इस बीच वह दोनों बच्चों को बेड पर बिठाकर शौचालय चली गईं। करीब 15 मिनट बाद वह वापस आई तो देखा कि उनकी झुग्गी में आग लगी थी। निशा बदहवास हो गई। उसने रोते-रोते शोर मचा दिया। पड़ोसी मदद को भागे। किसी तरह बाल्टियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बाद में झुलसी हुई हालत में बच्चों को बाहर निकालकर निजी वाहन से अस्पताल भेजा गया। पुलिस को रात करीब 11.30 बजे जीटीबी अस्पताल से खबर मिली। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची।

शकरपुर में शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर हुआ विवाद, 19 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या

दिल्ली । पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में डीजे पर डांस करने के दौरान हुए विवाद में एक युवक की उसके घर के सामने चाकू से वारकर हत्या कर दी गई। मृतक शिनाख्त विशाल (19) के रूप में हुई है। हत्या के बाद दोनों नाबालिग आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों को दबोच लिया। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला है कि विशाल की एक नाबालिग की बहन से दोस्ती थी। इसको लेकर पहले भी विवाद हुआ था। नाबालिग ने विशाल की पिटाई कर दी थी। मामला थाने भी पहुंचा था। शनिवार रात एक शादी समारोह में दोनों नाबालिग व विशाल डीजे पर डांस कर रहे थे। इस बीच वहां हुए विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। क्राइम टीम व एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एलबीएस मोर्चरी भेज दिया है। शकरपुर थाना पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की छानबीन कर रही है। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि विशाल अपने परिवार के साथ स्कूल ब्लॉक, शकरपुर में रहता था। इसके परिवार में पिता फूलचंद के अलावा मां तीजा, चार बहनें रानी, पूजा, आरती और योति के अलावा एक बड़ा भाई राहुल है। विशाल ऑटो चालक था। इसके पिता छोटा-मोटा निर्माणा का ठेका लेते हैं। विशाल की तीन बहनों की शादी हो चुकी है। शनिवार रात को बड़ी बहन पूजा की सहेली प्रियंका की घर के पास ही शिव मंदिर में शादी थी। रानी, पूजा और योति शादी में गई हुई थीं। देर अधिक होने की वजह से रात करीब 11 बजे विशाल बहनों को शादी समारोह से लेने के लिए शिव मंदिर चला गया। बहनों के कहने पर उसने शादी में पहले खाना खाया, बाद में वह डीजे पर डांस करने लगा। वहां पर दोनों नाबालिग आरोपी भी डांस कर रहे थे। विशाल व दोनों के बीच कहासुनी हुई तो विशाल वहां से आ गया। वह बुरी तरह डरा हुआ था। विशाल ने बहनों को भी सारी बात बताई। उसका कहना था कि नाबालिगों के पास चाकू हैं, वह उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। तीनों बहनें विशाल को लेकर घर की ओर जाने लगी। तीनों बहनें घर में दाखिल हो गई इस बीच विशाल घर के बाहर ही अपने एक दोस्त से बातचीत करने लगा। तभी परिजनों ने शोर सुना की विशाल को चाकू मार दिए गए हैं। परिवार विशाल को नजदीकी अस्पताल ले गया, जहां से एलबीएस रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचने पर विशाल को मृत घोषित कर दिया गया। बाद में पुलिस ने हत्या का मामला कर नाबालिगों को दबोच लिया। परिजनों का आरोप है कि है कि नाबालिगों ने दशहरा के आसपास विशाल की पिटाई की थी और उसे मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में विशाल ने थाने में भी शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

मनोज झा बोले- निष्पक्ष चुनाव असली मुद्दा; भाजपा ने किया पलटवार

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी में कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की विशाल रैली पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज कुमार झा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम निष्पक्ष चुनाव जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। बिहार चुनाव के दौरान हुए वित्तीय लेन-देन यह दिखाते हैं कि किसी भी तरह से वोट चुराने की कोशिश की गई। वहीं, कांग्रेस की रैली को लेकर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेस पार्टी की रैली पूरी तरह विफल होगी। कांग्रेस अपने ही कर्मों का फल भुगत रही है और यह बात वह जानती है। वह ईवीएम, एसआईआर और चुनाव आयोग पर दोष मढ़ना चाहते हैं।

कांग्रेस नेता खुद इन पर सवाल उठा रहे हैं और उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों को उठने से रोकने के लिए वे यह रैली कर रहे हैं। रैली में भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होगा। हुसैन ने कहा, कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि इसी दिल्ली की जनता ने उन्हें शून्य पर ला दिया था और बिहार की जनता ने उन्हें केवल छह सीट दी थीं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली पर ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा, जिस तरह देश में लोकतंत्र को बंधक रखा गया है। निश्चित तौर पर देश की यह भाजपा सरकार वोट चोरी की सरकार है। राहुल गांधी ने तमाम रायों में प्रेस वार्ता करके देश, मीडिया, लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से एक-एक वोटर और बूथ के बारे में जानकारी लाने का काम किया। मैं समझता हूं कि जो आज भाजपा है वो लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करके निश्चित तौर पर तानाशाही के रास्ते पर जाना चाहती है।

क्या राहुल गांधी दिल्ली की वोट चोरी के विषय में बात करेंगे - सौरभ भारद्वाज

आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस की रैली पर कहा, हमारी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं कि वे कोई भी जन जागृति का कार्य देश के अंदर करना चाहते हैं। लेकिन जिस दिल्ली के अंदर कांग्रेस वोट चोरी की शुरूआत कर रही है, इतनी बड़ी रैली कर रही है उसी दिल्ली में आज से एक साल पहले जब वोट चोरी हो रही थी, हमारे बड़े-बड़े नेता वोट चोरी के सबूत दिखा रहे थे तब कांग्रेस पार्टी चुप थी। आज एक साल बाद तक भी कांग्रेस उस पर चुप है। क्या राहुल गांधी दिल्ली की वोट चोरी के विषय में बात करेंगे या उससे बचेंगे? यदि बचते हैं तो उनका पूरा का पूरा नैरेटिव उनकी अपनी पार्टी के लिए है ये देश के लिए नहीं।

संचार साथी- साइबर सुरक्षा या साइबर निगरानी?

यह ऐप, जो शुरू में चोरी या खोए हुए फोन को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था, मोबाइल को एक ऐसा उपकरण बना देता जो उपयोगकर्ता को ट्रैक कर सके और देख सके कि वह किससे बात कर रहा है, उसके ईमेल और मोबाइल में क्या रखा है। दूसरे शब्दों में, यह एक पेगासस जैसी ऐप थी, जो सभी मोबाइल फोन में इंस्टॉल होती और फोन के सभी डेटा तक पहुंच सकती, जिसे उपयोगकर्ता हटा या बंद नहीं कर सकता। वकील और पूर्व सिविल जज भरत चुघ ने इसे ऑर्वेलियन कहा और बताया कि ऐसा गैर-हटाने योग्य ऐप जो कॉल, संदेश और स्टोरेज तक पहुंच सकता है, हमारे डिवाइस में स्थायी निगरानी का रास्ता खोल सकता है। संचार साथी का मूल उद्देश्य–खोए या चोरी हुए फोन को ढूंढना–काफी सरल था। हर मोबाइल में एक डिवाइस नंबर होता है, जिसे IMEI कहते हैं, जो आपके सिम नंबर से अलग होता है। संचार साथी सिस्टम किसी भी मोबाइल डिवाइस पर IMEI और सिम नंबर दोनों को ट्रैक करता है। अगर आपका मोबाइल खोया या चोरी हो गया है, तो उसका IMEI नंबर तुरंत भारतीय टेलीकॉम नेटवर्क में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और फोन केवल मालिक को वापस मिलने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के इस्तेमाल पर उपयोगकर्ताओं या प्राइवेसी समर्थक समुदाय की ओर से कोई गंभीर आपत्ति नहीं थी। ऐप का उद्देश्य स्पष्ट और सीमित था, और इसे इंस्टॉल करना और इस्तेमाल करना भी स्वैच्छिक था। समस्या तब शुरू हुई जब ऐप का दायरा सिर्फ खोए या चोरी हुए फोन को ट्रैक करने से बढ़कर पूरी निगरानी करने वाले उपकरण में बदल दिया गया। ऐसा उपकरण सुनिश्चित करता कि उपयोगकर्ता फोन या ऑनलाइन क्या करता है, इसका पूरा पता लगाया जा सके–वह कहां जाता है, किससे मिलता है–चाहे आमने-सामने या ऑनलाइन–सब कुछ ऐप द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। इसमें भी बुरी बात यह थी कि उपयोगकर्ताओं के पास ऐप को बंद करने या फोन से हटाने का कोई तरीका नहीं था। यानी प्रस्तावित संचार साथी ऐप की भूमिका मोबाइल को नेटवर्क पर ढूंढने से बदलकर उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने वाली बन जाती। यह मोबाइल को एक तरह का सुनने वाला उपकरण बना देती, जो जरूरत पड़ने पर यह सारी जानकारी सरकारी एजेंसियों तक पहुंचा सकता था। इसके जरिए फोन पर होने वाले सभी तरह के संवाद–चाहे वह व्हाट्सऐप हो, सिग्नल हो या कोई और ऐप–सरकारी अधिकारियों की पहुंच में आ सकते थे। भारत में 10 केंद्रीय एजेंसियां और राज्य सरकारों की पुलिस फोन कॉल्स को टैप कर सकती है, लेकिन इसके लिए तय कानूनी प्रक्रिया और केंद्र या राज्य के गृह सचिव की अनुमति जरूरी होती है। यानी किसी भी कारण से जांच के दायरे में आए व्यक्ति का फोन, कानूनी मंजूरी के बाद, आधिकारिक तौर पर टैप किया जा सकता है। नया प्रस्तावित संचार साथी ऐप सिर्फ फोन कॉल्स सुनने तक सीमित नहीं था। यह अधिकारियों को फोन के कैमरा या माइक्रोफोन तक एक्सेस देने, उसका लोकेशन ट्रैक करने और आसपास मौजूद अन्य फोन का पता लगाने की सुविधा देता, जिससे किसी भी फोन उपयोगकर्ता पर राज्य की एक सभी देखती आंख स्थापित हो जाती। इस ऐप को इंस्टॉल करने की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होती; सरकार के निर्देशों के अनुसार, इसे सभी भारत में बिकने वाले फोन में निर्माता द्वारा अनिवार्य रूप से पहले से ही डाल दिया जाता। इस तरह बेंथम का पैनऑप्टिकॉन आज के डिजिटल युग में सचमुच जीवित हो जाता, और हर नागरिक लगातार राज्य की सभी देखती आंख के अधीन होता! जेरेमी बेंथम, एक अंग्रेज दार्शनिक और विधिवेत्ता, ने सोचा कि कैसे ऐसी जेल बनाई जाए जिसमें गार्ड हमेशा कैदियों पर नजर रख सकें, ताकि अनुशासन बनाए रखा जा सके।

उनके इस विचार को पैनऑप्टिकॉन कहा गया, जिसमें सभी कैदी हमेशा गार्ड की दृष्टि में रहते। दिलचस्प बात यह है कि आज अधिकांश जेलों में कैमरे हैं, और मुकदमे में शामिल लोग भी लगातार कैमरा निगरानी में रहते हैं। यानी, बेंथम का पैनऑप्टिकॉन वास्तुकला के जरिए नहीं, बल्कि आधुनिक निगरानी तकनीक के जरिए हासिल किया गया। तो, मौजूदा संचार साथी ऐप क्या करता है, और दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित नए फंक्शन क्या थे, जिन्हें सार्वजनिक दबाव के बाद अब वापस ले लिया गया है? द वायर के साथ एक इंटरव्यू में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के अपार गुप्ता कहते हैं कि मौजूदा संचार साथी ऐप और वेबसाइट के जरिए आप जान सकते हैं कि आपके नाम पर कौन-कौन मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहा है या जो हैंडसेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वह असली है या नहीं।

सम्पादकीय...

विवाह...

यह महीना शादियों का रहा। कुछ खास शादियां कुछ आम सब तरह की शादियों में जाने का अवसर मिला। सब अलग-अलग अनुभव रहे परन्तु जो शादी बहुत चर्चा में रही और मुझे बहुत अच्छी लगी वो कथावाचक इन्द्रेश जी की है जो बहुत ही भव्यता और संस्कारों, रीति रिवाजों से हुई। जब मैंने इसकी रील देखी तो मुझे भी लगा कि काश मैं भी इस शादी में शामिल हो पाती। सभी बड़े-बड़े कथावाचक संत इकट्ठे थे, ऐसा लग रहा था मानों किसी देवता की शादी हो रही हो। सबसे खास बात थी कि घोड़ी, बारात, बैंड-बाजा सब चल रहा था परन्तु सभी राधे-राधे भजनों की तर्ज पर सभी बाराती नाच रहे थे। बड़ा ही सुन्दर दृश्य और धार्मिक संस्कारों वाला माहौल बना हुआ था। यानि सब कुछ किया गया परन्तु ईश्वर के नाम पर कितना आध्यात्मिक माहौल था। कथावाचक इन्द्रेश जी अपने माता-पिता का पूरा सम्मान कर रहे थे। यह बता रहे थे कि वो जो आज हैं वो अपने माता-पिता के कारण हैं। खासकर पिता के कारण जिनसे उन्होंने कथा करनी बड़ी छोटी उम्र से सीखी। आज के युवाओं के लिए यह बहुत बड़ा संदेश है। अभी कि इस जोड़े को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं जो बहुत ही गलत हैं। कभी किसी की निजी जिन्दगी में तांकझांक नहीं करनी चाहिए। और मुझे नहीं मालूम यह सच है या झूठ। अगर है भी तो मेरे मन में इन्द्रेश जी के लिए बड़ा सम्मान है। मैंने कभी उनकी कथा नहीं सुनी परन्तु अब जरूर सुनूंगी। मेरे विचार में एक कथा वाचक जो अपनी छोटी उम्र में लाखों लोगों के जीवन में संस्कार भर रहा है। अपने माता-पिता को सम्मान दे रहा है और अपनी बहनों का मान रख रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारे धार्मिक ग्रंथ विवाह को लेकर बहुत ही शुभ और अच्छे संदेशों के साथ भरे पड़े हैं जिन्हें एक प्रेरणा के तौर पर स्वीकार किया गया है और हम सबको आत्मसात् भी करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का सीता जी से स्वयंवर तथा इसी कड़ी में श्री कृष्ण का विवाह, भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी जी से विवाह या फिर भोले शंकर का पार्वती जी से विवाह यह अपने आप में एक बहुत पवित्र संदेश है। जोड़े की विष्णु-लक्ष्मी रूप में पूजा की जाती है। आचार्य लोग उदाहरण देकर इनसे संकल्प करवाते हैं। एक-दूसरे के साथ दुख-सुख में डटे रहने के संकल्प को लेकर सात बार अलग-अलग लकीरें पार करवाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर जो वायरल होता है उसे देख लोग पॉजिटिव-नैगेटिव राय भी बनाते हैं परन्तु मेरा मानना है कि आज की पीढ़ी विवाह पर पुराने संस्कार एवं आदर्शों का सम्मान भी जरूर करें। यह आज की नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता है विशेषकर उस समाज में जहां विवाह जैसे पवित्र बंधन को लेकर युवा पीढ़ी इसे तोड़ने की हद तक जा पहुंचे। तलाक अर्थात् डाइवोर्स जैसी घटनाएं भी उसी समाज में अगर बढ़ रही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि शादी के पवित्र आदर्शों को निभाया नहीं जा रहा इसलिए जरूरी यह है कि जरूरत से ज्यादा आजादी में नई पीढ़ी जिस सोच के साथ आगे बढ़ रही है उसकी तुलना की बजाए इस चीज पर ध्यान दिया जाए कि विवाह के पवित्र बंधन के धर्म को निभाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ धार्मिक तथाकथित बाबा और धार्मिक गुरुओं के चाल-चरित्र और आचरण इसलिए कुख्यात हुए हैं कि उन्होंने किसी भी शिष्या का शारीरिक शोषण किया। वह संत है या कुछ भी हस्ती हो लेकिन शादी के बाद गृहस्थ धर्म का पालन जरूरी है। यह सब मेरी व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे से जो शेयर कर रहे हैं यह उसका निचोड़ है। इस कड़ी में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का शिप्रा से विवाह भव्यता के मामले में भी काफी चर्चित है। लोग इस पर भी अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी कथावाचक ने भव्यता के साथ आयोजन किया है और सारा रुपया-धन अपना लगाया है लेकिन धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन भी शत-प्रतिशत हुआ है और बहुत लंबे अर्से बाद 101 पंडित आचार्य लोग अगर यह शादी करवा रहे हैं तो यह अपने आप में हमारे वेदों मंत्रोच्चारण पर आधारित उस धार्मिक महत्व को भी दर्शाते हैं जो हमारे देवी-देवताओं के विवाह के दौरान उदाहरण हुआ करते थे। शादी जीवन में एक मर्यादित संदेश देती है। यह दो दिलों का मिलन ही नहीं दो घरानों का एक ऐसा रिश्ता है जो परंपराओं और दुःख-सुख में साथ खड़ा रहने के लिए निभाया जाता है। इसका पालन किया जाना चाहिए। नकारात्मकता वाले पहलू को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और इस पवित्र शादी के बंधन में जो संदेश छिपे हैं जिसके दम पर हमारे दादा-दादी हमारे नाना-नानी आज तक संयुक्त परिवारों में चल रहे हैं उसका आधार विवाह का पवित्र बंधन ही है जिसे आज युवा पीढ़ी फटाफट और मौज मस्ती के इवेंट के रूप में मानती है। विवाह के नियम उसके आदर्श और उसकी पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती। कथावाचक इंद्रेश और शिप्रा के विवाह से यही संदेश दिया जाना चाहिए जिसे सकारात्मकता के साथ आत्मसात् किया जा सकता है।

टाइम-ऑफ-डे टैरिफ वह व्यवस्था है जिसमें बिजली की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि बिजली किस समय उपयोग की जा रही है

वैश्विक स्तरपर भारत का बिजली क्षेत्र अब एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।दशकों तक देश में बिजली बिलिंग की प्रणाली मुख्यतःयूनिट-आधारित रही, जहाँ उपभोक्ता द्वारा खपत की गई कुल बिजली के आधार पर शुल्क तय होता था,समय का कोई विशेष महत्व नहीं होता था। किंतु बदलती ऊर्जा आवश्यकताओं बढ़ती मांग, नवीकरणीय ऊर्जा केविस्तार और ग्रिड प्रबंधन की जटिलताओं ने इस परंपरागत मॉडल को अप्रासंगिक बना दिया है।इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार और विद्युत नियामक संस्थाओं ने समय आधारित बिजली टैरिफ (टाइम ऑफ़ डे टैरिफ़) को लागू करने का संभावित निर्णय की ओर अग्रसर है, जिसके तहत दिन, रात, सुबह और शाम अलग -अलग दरों पर बिजली बिल लगेगा। यह प्रणाली अगले 3 से 6 महीनों में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू की जा रही है।यह परिवर्तन कोई तात्कालिक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सुदृढ़ कानूनी ढांचा, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति, टैरिफ नीति संशोधन,और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों पर आधारित रणनीति है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 को आधुनिक बिजली व्यवस्था की आवश्यकता और ऊर्जा संक्रमण की राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप तैयार किया गया एक प्रमुख सुधारात्मक प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना,नियामकीय ओवरसाइट सुदृढ़ करना और उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक खपत के अनुसार भुगतान के लिए प्रेरित करना है।विधेयक की यह नींव पारंपरिक यूनिफॉर्म-टैरिफ मॉडल से हटकर मांग-आधारित समय- संवेदी कीमत निर्धारण की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है,जिसका सबसे निर्णायक उपकरण समय-आधारित टैरिफ है।विधेयक की प्रमुख धारणाएँ, टीओडी टैरिफ का वैज्ञानिक व आर्थिक तर्क, कार्यान्वयन चुनौतियाँ स्मार्ट मीटरिंग और ग्रिड-समर्थन तकनीकों की भूमिका, उपभोक्ता-प्रभाव (वंचित वर्गों सहित) मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से हम इसका विश्लेषण करेंगे। साथियों बात अगर हम टाइम- ऑफ-डे टैरिफ क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको समझने की करें तो, टाइम -ऑफ-डे टैरिफ वह व्यवस्था है जिसमें बिजली की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि बिजली किस समय उपयोग की जा रही है। उदाहरण के लिए,जब बिजली की मांग अत्यधिक होती है,जैसे शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक,उस समय दरें अधिक होंगी। वहीं जब मांग कम होती है,जैसे देर रात या दोपहर,तब बिजली सस्ती होगी। भारत में बिजली की मांग दिन के अलग- अलग समय पर अत्यंत असमान रहती है। पीक आवर्स में ग्रिड पर भारी दबाव पड़ता है,महंगे पावर प्लांट चालूकरने पड़ते हैं और कभी-कभी बिजली कटौती तक करनी पड़ती है। इसके विपरीत ऑफ-पीक समय में उत्पादन क्षमता का बड़ा हिस्सा निष्क्रिय रहता है।टीओडी टैरिफ का उद्देश्य मांग को संतुलित करना, ग्रिड स्थिरता बढ़ाना,और उपभोक्ताओं को समय के अनुसार खपत बदलने के लिए प्रेरित करना है।भारत में बिजली क्षेत्र का मूल कानूनी ढांचा विद्युत अधिनियम, 2003 (इलेक्ट्रिसिटी एक्ट,2003) है। यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को बिजली उत्पादन, वितरण और टैरिफ निर्धारण के लिए व्यापक अधिकार देता है। अधिनियम की धारा 61 और 62 विशेष रूप से टैरिफ निर्धारण से संबंधित हैं, जिनमें कहा गया है कि टैरिफ आर्थिक दक्षता, उपभोक्ता हित, और संसाधनों के कुशल उपयोग को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा।समय आधारित टैरिफ इसी अधिनियम की भावना के अनुरूप है, क्योंकि यह बिजली संसाधनों के बेहतर उपयोग और लागत-आधारित मूल्य निर्धारण को प्रोत्साहित करता है।अधिनियम किसी एक समान दर की बाध्यता नहीं लगाता, बल्कि नियामक आयोगों को नवाचार की स्वतंत्रता देता है। साथियों बात अगर हम राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016 और 2023 संशोधन की भूमिका इसको समझने की करें तो, टाइम -ऑफ-डे टैरिफ को वास्तविक रूप से अनिवार्य बनाने का कार्य राष्ट्रीय टैरिफ नीति (टैरिफ पालिसी) के माध्यम से किया गया। 2016 की टैरिफ नीति में पहली बार संकेत दिया गया कि बड़े उपभोक्ताओं के लिए समय आधारित टैरिफ अपनाया जाना चाहिए। किंतु यह प्रावधान सीमित और वैकल्पिक था।वास्तविक परिवर्तन 2023 में किए गए टैरिफ नीति संशोधन से आया। इस संशोधन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि,डिस्कॉम को सभी उपभोक्ताओं के लिए चरणबद्ध तरीके से टाइम ऑफ़ डे टैरिफ़ लागू करना होगा।(1) स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था प्राथमिकता से लागू की जाएगी।(2)राज्य विद्युत नियामक आयोगों को पीक और ऑफ-पीक घंटों की अधिसूचना करनी होगी।यह संशोधन ही वह प्रत्यक्ष नीति आधार है जिसके तहत अब देशभर में दिन-रात के हिसाब से बिजली दरें तय की जा रही हैं। साथियों बात अगर हम राष्ट्रीय विद्युत नीति और ऊर्जा संक्रमण का संदर्भ,राज्य विद्युत नियामक आयोगों की भूमिका,इसको समझने की करें तो,भारत की राष्ट्रीय विद्युत नीति का मूल उद्देश्य सस्ती, विश्वसनीय और सतत बिजली उपलब्ध कराना है।नीति यह स्वीकार करती है कि भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था में सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी लगातार बढ़ेगी। चूंकि ये स्रोत समय-निर्भर होते हैं, इसलिए पारंपरिक फ्लैट टैरिफ उनके अनुकूल नहीं है।दिन में जब सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, उस समय बिजली सस्ती होनी चाहिए। वहीं रात में, जब सौर उत्पादन नहीं होता, दरें स्वाभाविक रूप से अधिक होंगी। टीओडी टैरिफ इसी तार्किक ऊर्जा संतुलन को लागू करता है।टाइम-ऑफ-डे टैरिफ बिना स्मार्ट मीटर के संभव नहीं है। इसी कारण भारत सरकार ने रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत करोड़ों स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता की बिजली खपत को रियल-टाइम में रिकॉर्ड करते हैं और यह बताने में सक्षम होते हैं कि किस समय कितनी बिजली उपयोग हुई।आरडीएसएस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य ही यह है कि टैरिफ को डायनेमिक, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाया जाए।टीओडी टैरिफ इसी योजना का स्वाभाविक परिणाम है।राज्य विद्युत नियामक आयोगों की भूमिका-हालाँकि नीति और दिशा -निर्देश केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन वास्तविक टैरिफ निर्धारण का अधिकार राज्य विद्युत नियामक आयोगों के पास होता है। प्रत्येक राज्य अपने भौगोलिक, आर्थिक और खपत पैटर्न के अनुसार पीक और ऑफ-पीक समय निर्धारित करेगा।इसका अर्थ यह है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में पीक आवर्स अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत समान रहेगा -भीड़ वाले समय में महंगी बिजली और खाली समय में सस्ती बिजली। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय अनुभव और भारत की स्थिति इसको समझने की करें तो,टाइम-ऑफ-डे टैरिफ कोई भारतीय प्रयोग नहीं है।अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया,जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह प्रणाली वर्षों से लागू है। इन देशों के अनुभव बताते हैं कि टीओडी टैरिफ से(1)पीक डिमांड में 10-20प्रतिशत तक कमी आई (2) ग्रिड फेल्योर और ब्लैकआउट की घटनाएँ घटीं (3) उपभोक्ताओं की ऊर्जा दक्षता बढ़ी,भारत अब उसी वैश्विक ऊर्जा सुधार पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपने सामाजिक- आर्थिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए।उपभोक्ताओं पर प्रभाव, अवसर और चुनौतियाँ,इस नई प्रणाली से उपभोक्ताओं को यह समझना होगा कि बिजली अब केवल कितनी नहीं, बल्कि कब उपयोग की जा रही है। जो उपभोक्ता वाशिंग मशीन, पानी की मोटर, चार्जिंग और अन्य भारी उपकरण ऑफ-पीक समय में चलाएंगे, उनके बिल कम होंगे।हालाँकि शुरुआती दौर में जागरूकता की कमी, तकनीकी समझ और व्यवहारिक बदलाव चुनौती बन सकते हैं। इसलिए नीति में स्पष्ट किया गया है कि टीओडी टैरिफ क्रमिक रूप से लागू किया जाएगा, न कि एक झटके में। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि नियम आधारित सुधार,न कि तात्कालिक निर्णय,भारत में समय आधारित बिजली टैरिफ किसी एक आदेश या घोषणा का परिणाम नहीं है। यह विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय टैरिफ नीति (संशोधित 2023), राष्ट्रीय विद्युत नीति, और आरडीएसएस जैसी योजनाओं के संयुक्त प्रभाव से उभरा एक संरचनात्मक सुधार है।यह प्रणाली भारत को न केवल ऊर्जा दक्ष बनाएगी, बल्कि उसे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की मुख्यधारा में भी स्थापित करेगी। आने वाले वर्षों में बिजली केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि समय-संवेदी आर्थिक संसाधन बन जाएगी–और यही इस ऐतिहासिक बदलाव का मूल उद्देश्य है।

भाजपाईयों ने लाइव देखा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति का कार्यक्रम

मुरादाबाद। नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की घोषणा कार्यक्रम को महानगर कार्यालय बुद्धि विहार पर महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला के नेतृत्व में लाइव देखा। संगठन पर्व के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के महाराज गंज लोकसभा सीट से सात बार के सांसद केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वित्त रा'य मंत्री नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की घोषणा लोहिया विश्वविद्यालय आशियाना लखनऊ में केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वाणि'य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने की घोषणा होते ही पंडाल का सारा वातावरण तालियों से गूंज उठा भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों से सारा वातावरण गूंज उठा। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की घोषणा एवं ताजपोशी को लाइव देखने वालों में महानगर कार्यालय पर क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा,महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला,एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त,एमएलसी गोपाल अंजान,महानगर महामंत्री नत्थू राम कश्यप दिनेश शीर्षवाल, पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता व राहुल सेठी जिला महामंत्री कमल प्रजापति हरज्ञान सिंह, नवदीप टंडन, दिनेश सिसोदिया, हेमराज सैनी, राहुल शर्मा, विशाल त्यागी,अंजू लोचब,चंद्र प्रजापति,धर्मेश सैनी अभिषेक चौबे, भूदेव सिंह,शम्मी भटनागर, सुनीता शर्मा,शशी किरण,सर्वेश पटेल,मुनींद्र कुमार, विपिन प्रजापति,मिथुन शर्मा,सोमपाल प्रजापति,योगेश गुप्ता,दीक्षांत चौधरी, अश्वनी शर्मा,सुमित कुमार,हेमा खत्री,इला सिंह, नीलम रस्तोगी,उर्वशी,सौरभ सक्सैना,हरिओम सैनी,बंटी सैनी, सुमित चौहान आदि महानगर मंडल मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी पार्षदगण शामिल रहे।

काकोरी के बलिदानियों की स्मृति में हुई भाषण प्रतियोगिता

मुरादाबाद। समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद पर महानगर के अनेक विद्यालयों के प्रतिभागियों की काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों ने की स्मृति में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

भाषण प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में आर्य विद्वान अमरनाथ आर्य, प्रवक्ता डा अनुपम गुप्ता और डा आलोक कुमार रहे। भाषण प्रतियोगिता के विषय देश की आजादी में काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की भूमिका पर प्रतिभागियों ने क्रांतिकारियों की देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत ओजस्वी भाषण देकर आजादी का भावनात्मक वातावरण प्रस्तुत किया। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के आर्य समाज शाहजहांपुर में एक साथ रहने को हिन्दू मुस्लिम समन्वयक का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। रामप्रसाद बिस्मिल के गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है... गाकर जोश पैदा कर दिया। दूसरे प्रतिभागी ने ट्रेन एक्शन उपरांत अपने ही भीतर घातियों द्वारा क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी पर कहा कि -जिन्हे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वहीं अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। रामप्रसाद बिस्मिल का क्रांतिकारी बनने में आर्य समाज के विशेष योगदान का भी प्रतिभागियों ने उल्लेख किया। चंद्रशेखर आजाद के जीवन भर आजाद रहने और अदालत द्वारा सजा सुनाते समय उनके परिचय का संस्मरण सुनाकर वातावरण देशभक्ति भावना से ओत-प्रोत कर दिया। भाषण प्रतियोगिता का परिणाम और पुरस्कार वितरण 21दिसम्बर को काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदान दिवस पर किये जाने की घोषणा के साथ प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। प्रतियोगिता का संचालन रमेश सिंह आर्य एडवोकेट ने किया।
आभार व्यक्त प्रधान डा अभय श्रोत्रिय ने किया।

क्षत्रिय समाज में युवाओं में फैल रही कुरीतियां दूर करने पर दिया ज़ोर

मुरादाबाद।

ग्राम मूंढापांडे के गौतम पैलेस में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मुरादाबाद द्वारा युवा परिचय एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय युवाओं ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करना था। सम्मेलन का शुभारंभ भगवान राम और क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, ठाकुर राहुल सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर देवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे और प्रदेश महामंत्री ठाकुर यशपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा ठाकुर अजय सिंह राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राणा एवं प्रदेश मंत्री ठाकुर अशोक कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने क्षत्रिय समाज में युवाओं में फैल रही कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया। युवाओं से समाज के उत्थान के लिए आगे आने का आह्वान किया और कहा कि समाज की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। विधायक ने आगे कहा कि क्षत्रिय का वास्तविक अर्थ क्षेत्र की सेवा करना है। हम अपने साथ साथ अपने समाज की चिंता भी करें। क्षत्रिय समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए युवाओं को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपनी मेहनत और लगन से पहचान बनानी होगी। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए राजनीतिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। नियोजक राहुल सिंह ने समाज के उत्थान के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरी न मिलने पर निजी क्षेत्र में काम करने या अपना व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से सशक्त बनने की सलाह दी। ठाकुर देवेंद्र सिंह ने समाज के राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में पिछड़ने पर चिंता व्यक्त की और सामूहिक प्रयासों से उत्थान की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह बब्बू और संचालन जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने की। कार्यक्रम में युवा जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, विक्रम सिंह उर्फ रिंकू ठाकुर,कशिश चौहान, शगुन चौहान, संजीव चौहान, मनोज तोमर, राजीव चौहान, सोमपाल सिंह, अखिल चौहान, जोगेंद्र चौहान, विशाल सिंह, सचिन सिंह, ओम चौहान, शेखर राणा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

आदर्श कला संगम ने किया विभूतियों का सम्मान

मुरादाबाद।

जनपद की प्रमुख सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था गत 24 वर्षों से कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में जनपद के विभिन्न महानुभावों को सम्मानित करती है। इस वर्ष संस्था द्वारा 25वां सम्मान समारोह दिव्य सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम देवी सरस्वती के समक्ष मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर हरवंश दीक्षित कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ केके मिश्रा जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राजेश रस्तोगी एवं रवि अरोरा ने दीप प्र'वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथि गण का स्वागत करते हुए डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा साल भर में अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं तथा यह संस्था सन 1966 ई से मुरादाबाद शैली की रामलीला के मंचन में निरंतर सक्रिय है जिसकी पूरे देश के अंदर भूरि भूरि प्रशंसा की जाती है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश की प्रमुख सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था आदर्श कला संगम द्वारा 25 वें सम्मान समारोह में मास्टर फिदा हुसैन नरसी स्मृति सम्मान डॉ0 रामानन्द बाजपेई को, प्रसिद्ध रंगकर्मी बलवीर पाठक स्मृति सम्मान रंगकर्मी राजेश सक्सेना को, पंडित वाचस्पति शर्मा स्मृति सम्मान मेजर डॉ0 मीनू महरोत्रा हिन्दू महाविद्यालय मुरादाबाद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरेन्द्र कुमार अरोरा स्मृति सम्मान सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉ0 बृजपाल सिंह यादव को, वरिष्ठ पत्रकार एवं सम्पादक हिन्दी दैनिक युगबन्धु स्मृति सम्मान वरिष्ठ पत्रकार एवं उपज के महामंत्री कुमार देव को, प्रोफेसर महेन्द्र प्रताप स्मृति सम्मान डॉ0 राजीव कुमार शर्मा को, वरिष्ठ नवगीतकार माहेश्वर तिवारी स्मृति सम्मान प्रख्यात कवि योगेन्द्र वर्मा व्योम को, पंडित बृजगोपाल व्यास स्मृति सम्मान पंडित ज्ञान चन्द शर्मा को, पंडित सुधीश व्यास स्मृति सम्मान सुधा सक्सेना को प्रदान किया गया। मंचासीन अतिथिगण द्वारा विभूतियों को सम्मानित करते हुए समाज के प्रति उनके योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। सम्मान के रूप में सम्मान पत्र के साथ-साथ स्मृति चिन्ह,श्रीफल , मोतियों की माला तथा शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरवंश दीक्षित जी ने इस अवसर पर कहा कि संस्था के द्वारा इस प्रकार के कार्य किया जाना वास्तव में प्रशंसनीय है। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ केके मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह संस्था अपने क्रियाकलापों से समाज को सकारात्मक दिशा की ओर ले जा रही है। विशिष्ट अतिथि राजेश रस्तोगी ने संस्था को साधुवाद देते हुए कहा की इस प्रकार के अ'छे कार्यों से संस्था का समाज में मानऔर सम्मान बहुत बढ़ रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादस्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

नेपाल में जल्द फिर से चला करेंगे 100 से ऊपर के भारतीय नोट, अभी डॉलर और रुपये को लेकर ये हैं नियम

नई दिल्ली।

नेपाल करीब एक दशक बाद 100 रुपए से ऊपर के भारतीय नोटों को चलन में लाने की योजना बना रहा है। यह जानकारी एक नेपाली अखबार द्वारा प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट में दी गई। इस हिमालयी पड़ोसी देश में करीब 10 साल से उच्च मूल्य के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगा है। द काठमांडू पोस्ट में नेपाली अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि इस कदम से भारत यात्रा करने वाले नेपाली प्रवासी श्रमिकों के साथ-साथ दोनों देशों के छात्रों, तीर्थयात्रियों, चिकित्सा आगंतुकों और पर्यटकों की मुद्रा संबंधी समस्याओं में काफी राहत मिलेगी। नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने कहा, इसको लेकर हम नेपाल गजट में अधिसूचना प्रकाशित करने की तैयारी में हैं। उसके बाद नए नियम के बारे में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सर्कुलर जारी करेंगे। पौडेल ने कहा कि इस नए नियम की आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नेपाल में लंबे समय से उच्च मूल्य के भारतीय नोटों पर

प्रतिबंध हटाने की मांग उठ रही थी, क्योंकि इससे पर्यटन उद्योग, खासकर हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को नुकसान हो रहा था। भारतीय पर्यटक बिना जानें नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके चलते कई बार गिरफ्तारी और जुर्माने का भी सामना करना पड़ता था। यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (निर्यात और आयात मुद्रा) नियमों में 28 नवंबर, 2025 को किए गए संशोधन के बाद आया है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति नेपाल में 100 रुपए तक के किसी भी मूल्य के भारतीय नोट लेकर जा सकता है और वापस ला सकता है। साथ ही वह 100 रुपए से अधिक मूल्य के 25,000 रुपए तक के नोट दोनों दिशाओं में ले जा सकता है। अभी, नेपाल आने वाले टूरिस्ट, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, बिना बताए 5,000 डॉलर या दूसरी बदली जा सकने वाली करेंसी में इसके बराबर की रकम ला सकते हैं। इससे अधिक रकम होने पर कस्टम्स में बतानी होगी, और टूरिस्ट 5,000 डॉलर से यादा रकम बाहर नहीं ले जा सकते। फिलहाल, भारत नेपाल के लिए टूरिस्ट का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है।

संसदीय समिति ने भूमिगत कोयला खनन परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रक्रिया आसान करने की सिफारिश की

नई दिल्ली। एक संसदीय समिति ने भूमिगत कोयला खनन की अनुमति के लिए नीति को सरल बनाने और मानकीकृत प्रोटोकॉल अपनाने का सुझाव दिया है। समिति का कहना है कि बड़ी खुली कोयला खदानों जैसी जटिल मंजूरी प्रक्रिया लागू किए जाने से कम पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं में भी देरी होती है। सरकार ने 2030 तक भूमिगत कोयला खदानों से 10 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भूमिगत कोयला खनन से सतह पर होने वाला व्यवधान न्यूनतम रहता है, जिससे भूमि, वन और बुनियादी ढांचे का संरक्षण होता है। इसके साथ ही भूमि पुनर्वास की लागत और अप्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आती है। यह पद्धति उच्च गुणवत्ता वाले गहरे कोयला भंडार तक पहुंच की अनुमति देती है और मौसम की परवाह किए बिना पूरे वर्ष संचालन सुनिश्चित करती है। रिपोर्ट में कहा गया, कम पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, कई भूमिगत परियोजनाओं को बड़ी खुली कोयला खदानों जैसी ही मंजूरी और दस्तावेजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे परियोजनाओं में देरी होती है। इसलिए समिति ने भारत में भूमिगत कोयला खनन प्रथाओं के लिए नीति को सरल बनाने और मानकीकृत प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके अलावा, समिति ने खुले में खनन के लिए भी एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली के तहत मानक संदर्भ शर्तें (टीओआर) और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) लागू करने की सिफारिश की है।

भारत टैक्स पारदर्शिता में मजबूत अगुवा : विदेशी टैक्स चोरी पर 29 हजार करोड़ का हुआ खुलासा, ओईसीडी ने की सराहना

नई दिल्ली। भारत ने विदेशी टैक्स चोरी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बात का दावा वैश्विक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के एक शीर्ष अधिकारी ने की। उन्होंने कहा कि भारत विदेशी टैक्स चोरी (ऑफशोर टैक्स एवेजन) के खिलाफ पारदर्शिता लागू करने में दुनिया के मजबूत देशों में शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की पारदर्शी टैक्स नीतियों और आयकर विभाग के हालिया अभियान से 29 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित विदेशी संपत्तियों का खुलासा हुआ है।

यह भारत की मजबूत वैश्विक भूमिका और सख्त टैक्स व्यवस्था को दर्शाता है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक सक्षात्कार में ओईसीडी की टैक्स पारदर्शिता और सूचना आदान-प्रदान से जुड़े ग्लोबल फोरम की सचिवालय प्रमुख जायदा मैनाटा ने यह बात कही। वह हाल ही में 2 से 4 दिसंबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल फोरम की वार्षिक बैठक में शामिल होने भारत

आई थीं। बता दें कि इस फोरम के 172 देश सदस्य हैं। विदेशी टैक्स चोरी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए भारत की तारिफ क्यों हुई? इस बात ऐसे समझा जा सकता है, क्योंकि मैनाटा ने कहा कि भारत 2009 से ही टैक्स पारदर्शिता के लिए ग्लोबल फोरम के काम में सक्रिय सहयोग दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्स पारदर्शिता का मजबूत समर्थक है और ऑफशोर टैक्स चोरी के खिलाफ लगातार काम कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नई दिल्ली में 2025 की ग्लोबल फोरम बैठक की मेजबानी करना भी भारत की इसी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ओईसीडी अधिकारी ने आगे बताया कि भारत ने ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन (एईओआई) और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (सीआरएस) को लागू करने के लिए जरूरी कानूनी ढांचा तैयार कर लिया है और इसका सही तरीके से पालन भी कर रहा है। इस व्यवस्था के तहत अलग-अलग देशों की टैक्स एजेंसियां एक-दूसरे के साथ विदेशी बैंक खातों और संपत्तियों की जानकारी साझा करती हैं, ताकि टैक्स चोरी रोकी जा सके। इसके साथ ही मैनाटा ने भारत सरकार के एनयूडीजीई (नॉन-इंट्रूसिव यूज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल) कार्यक्रम की खास तौर पर तारीफ की। उन्होंने बताया कि इस अभियान से विदेशी संपत्ति बताने वाले करदाताओं की संख्या में 45.17व की बढ़ोतरी हुई। साथ ही लगभग 29,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी संपत्तियां घोषित की गई और 1,089 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी आय भी सामने आई। गौरतलब है कि यह अभियान आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नवंबर 2024 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य उन करदाताओं को सचेत करना था, जिनकी विदेशी संपत्तियों की जानकारी दूसरे देशों से भारत को मिली थी, लेकिन उन्होंने उसे अपने आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया था। इस अभियान के तहत करीब 24,678 करदाताओं ने अपने रिटर्न दोबारा देखे और विदेशी संपत्तियों व आय का खुलासा किया। सीबीडीटी ने ऐसा ही दूसरा अभियान आकलन वर्ष 2025-26 के लिए भी शुरू कर दिया है।

इंडिगो के खिलाफ क्लास एक्शन की तैयारी? विमानन विशेषज्ञ का दावा- सैकड़ों लोग करेंगे मुकदमा

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस इन दिनों देश में प्रमुख तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिकरत लोग इंडिगो को लेकर खूब सारी बातचीत भी कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस से जुड़े हालिया संकट के बाद भले ही कंपनी की स्थिति अब सामान्य हो गई हो, लेकिन इससे प्रभावित यात्रियों की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। ऐसे में अब सैकड़ों लोग एक साथ एयरलाइंस के खिलाफ क्लाश एक्शन यानी मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का दावा विमानन विशेषज्ञ संजय लाजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से किया है। लाजर ने पोस्ट में बताया कि बड़ी संख्या में यात्री अब भी मदद के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि यह जानकारी वह जनहित में साझा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंडिगो संकट से प्रभावित 829 यात्रियों का एक समूह बन चुका है, जो अब मुआवजे की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। अपनी पोस्ट में विमान विशेषज्ञ संजय लाजर ने इंडिगो संकट के दौरान प्रभावित लोगों से एक ग्रुप में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि, जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई, जो हवाई अड्डों पर फंसे रहे या किसी भी तरह से इस अव्यवस्था से प्रभावित हुए, वे इस समूह से जुड़ सकते हैं। लाजर ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रुप में जुड़ने के लिए यात्रियों को एक ईमेल भेजना होगा या दिए गए गूगल फॉर्म को भरना होगा, ताकि वे सामूहिक रूप से कानूनी कारंवाई कर सकें। संजय लाजर ने यह भी कहा कि यदि किसी को इस प्रक्रिया से जुड़ा कोई सवाल है, तो वे सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे जवाब देकर अपनी शंका पूछ सकते हैं। गौरतलब है कि क्लास एक्शन एक तरह की कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें एक या यादा व्यक्ति अपने समान दावे के साथ एक समूह के रूप में एक ही मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आरोपित कंपनी पर कुप्रबंधन और धोखाधड़ी जैसे कृत्यों के के लिए सामूहिक मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। सर्वे के मुताबिक अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस, साउथवेस्ट एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस पर इस तरह के मुकदमे किए गए थे। क्लास एक्शन का मकसद न्याय की प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाना है, जिससे समान मामलों में एक ही निर्णय लिया जा सके और न्यायालयों पर बोझ कम हो।

आईएटीए : जीपीएस हस्तक्षेप की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय, वैश्विक एयरलाइंस समूह ने पायलटों को दी सतर्क रहने की सलाह

जिनेवा/नई दिल्ली।

वैश्विक एयरलाइंस संगठन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) ने कहा कि उड़ानों के दौरान जीपीएस प्रणाली को बाधित करने घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो चिंता का विषय है और पायलटों को पहले से यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आईएटीए दुनिया की करीब 360 एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक हवाई यातायात का 80 हिस्सा से यादा हिस्सा संभालती हैं। एअर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट भी इस संगठन का हिस्सा हैं।

हाल के समय में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमृतसर, हैदराबाद, बंगलूरू और चेन्नई हवाई अड्डे पर भी जीपीएस स्पूफिंग (गलत सिग्नल भेजकर भ्रमित करना) और इंटरफेरेंस (बाधा डालना) की घटनाएं सामने आई हैं। इस हफ्ते जिनेवा में हुई बातचीत के दौरान आईएटीए के अधिकारियों ने कहा कि जीपीएस प्रणाली में बाधा डालने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आईएटीए के महानिदेशक विली वॉल्श ने कहा कि गलत सिग्नल

भेजकर भ्रमित करने और बाधा पहुंचाने की घटनाओं के कारण पालयटों को ऑपरेशन के दौरान यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह समस्या अब पूरी दुनिया में मौजूद है। अंतरराष्ट्रीय विमानन संगठन (आईसीएओ) जीएनएसएस (वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली) की स्पूफिंग को अंतरराष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस का एक रूप मानता है। आईएटीए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संचालन और सुरक्षा) निक कैरिन ने कहा कि शुरुआत में ऐसी घटनाएं पश्चिम एशिया में देखी गई थीं और रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद यह पूर्वी यूरोप में भी बढ़ीं। उन्होंने कहा, अब भारत, एशिया और वेनेजुएला में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आईएटीए के आंकड़ों के अनुसार, प्रति 1,000 उड़ानों पर जीपीएस सिग्नल खोने की दर 2022 में 31 थी, जो 2025 में बढ़कर 59 होने का अनुमान है। ये आंकड़े फ्लाइट डेटा एक्सचेंज (एफडीएक्स) से लिए गए हैं, जो वैश्विक विमानन डाटा प्रबंधन कार्यक्रम का हिस्सा है और इसमें कई एयरलाइंस अपना डाटा साझा करती हैं। 2024 में यह दर 56 थी, जिससे लगातार बढ़ोतरी का रुझान दिखता है। निक कैरिन ने कहा कि यह बढ़ोतरी गंभीर और चिंताजनक है और इससे साफ होता है कि जीपीएस प्रणाली में बाधा डालने की घटनाएं केवल उड़ानों की संख्या बढ़ने के कारण नहीं हो रही हैं।

पड़ोसी की हत्या में शामिल महिला 11 साल बाद गिरफ्तार, हरियाणा के झजर में छिपी थी परवीन

नई दिल्ली। बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र में पानी गिरने को लेकर विवाद में अपने पति और अन्य लोगों के साथ मिलकर पड़ोसी की बेरहमी से हत्या करने वाली महिला को आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वह पिछले 11 वर्षों से भगोड़ा घोषित थी और लगातार अपने ठिकाने बदलकर फरार चल रही थी। आरोपित महिला की पहचान गांव मित्राओं की परवीन उर्फ प्रीति के रूप में हुई है। हालांकि, मामला दर्ज होने के बाद ही उसके पति और अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुताबिक, 30 जुलाई 2014 को नजफगढ़ निवासी विनीत नामक युवक सबमर्सिबल पंप से पानी भर रहा था तभी गलती से कुछ पानी पड़ोसन परवीन की तरफ गिर गया। इससे गुस्साई परवीन ने गाली-गलौज करते हुए झगड़ा शुरू कर दिया और पति, सुरेश उर्फ मुन्नू को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर पीड़ित के परिजन रवि, सचिन, नवीन और अन्य बीच-बचाव कराने पहुंचे ही थे कि सुरेश ने अपने कई साथियों, जिनमें राहुल उर्फ लाला, संदीप उर्फ सरदारजी, विक्रांत उर्फ कालू, मुकेश उर्फ मुक्का, सागर और अन्य को बुलाया। वे चाकू, लोहे के पाइप, लकड़ी की छड़ी और टूटे हुए बेसबाल बैट जैसे हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे और रवि और बीच-बचाव करने वाले परिवार के सदस्यों पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान, संदीप ने रवि को पीछे से पकड़ा और राहुल ने उसके सीने पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। वारदात के बाद सुरेश, परवीन, राहुल, संदीप, विक्रांत, मुकेश, सागर और अन्य मौके से भाग निकले। घायल रवि को राव तुला राम अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और जांच के दौरान, परवीन को छोड़कर सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पकड़ने के लिए मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। इस दौरान एएसआइ अशोक और हेड कॉन्स्टेबल परमजीत को गुप्त जानकारी मिली कि परवीन हरियाणा के झजर में छिपी हुई है। सूचना पर एसीपी भगवती प्रसाद की देखरेख में और इंस्पेक्टर गुलशन यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने परवीन की सही लोकेशन का पता लगाया और 12 दिसंबर को छापेमारी करते हुए उसे झजर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि पड़ोसियों- बिजेंद्र, उसकी पत्नी बाला और उनके बेटे विनीत के साथ सड़क पर जानबूझकर पानी गिराने के मुद्दे पर अक्सर झगड़े होते थे। 30 जुलाई 2014 को विनीत ने फिर से उनकी तरफ पानी गिराया, जिससे झगड़ा बढ़ गया। हमले के तुरंत बाद, परवीन और उसके पति सहित आरोपित मौके से भाग गए। अगली सुबह, परवीन को पता चला कि रवि की चोटों के कारण मौत हो गई है। उसने बताया कि पति की गिरफ्तारी के बाद, वह अपने नाबालिग बेटे के साथ भाग गई और 11 साल से अधिक समय तक कानून से बचने के लिए हरियाणा में रिश्तेदारों के घरों में छिपी रही।

नितिन नबीन होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

बिहार सरकार में मंत्री हैं; नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे

नई दिल्ली।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है. बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. जेपी नड्डा के बाद अब पार्टी की जिम्मेदारी वही संभालेंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से जारी लेटर में कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

नितिन नबीन एक युवा और संगठनात्मक अनुभव के धनी नेता हैं- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, 'नितिन नबीन जी ने खुद को भाजपा के एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया है. वह एक युवा, कर्मठ और संगठनात्मक अनुभव के धनी नेता हैं, जिनका बिहार में एक विधायक और मंत्री के रूप में कई कार्यकालों का एक प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया है.' उन्होंने कहा, 'वह अपने विनम्र स्वभाव और जमीन से जुड़ी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक मजबूत करेगी. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई

बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन के भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'बिहार की धरती से आने वाले युवा और ऊर्जावान नेता श्री नितिन नबीन को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई. वे एक कर्मठ कार्यकर्ता और कल्पना क्षमता के धनी व्यक्ति हैं.' उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक नेतृत्व में वे भाजपा को सफलता की नई बुलंदियों तक ले जाने में अवश्य सफल होंगे. उनके कार्यकाल की सफलता के लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं.'

कौन हैं नितिन नबीन?

बिहार सरकार में PWD मंत्री नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं. इस बार बिहार की बांकीपुर सीट से पांचवीं बार विधायक बने हैं. उन्होंने 2006 में उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी. पिता के निधन के बाद उन्होंने सियासी विरासत को संभाला है. इसके बाद 2010, 2015 और 2020 के बाद अब 2025 में भी जीत का परचम लहराया है. पहली बार 9 फरवरी 2021 को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें पथ निर्माण मंत्री बनने का मौका मिला था.

पंकज चौधरी बने उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष, योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं ने दी बधाई

लखनऊ। महाराजगंज से सातवीं बार लोकसभा सांसद और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। शनिवार को उनके खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल ने रविवार को पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी के 17वें अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। 1980 में बीजेपी उत्तर प्रदेश के गठन के बाद से पंकज चौधरी यह पद संभालने वाले 17वें नेता हैं। इस दौरान राष्ट्रीय परिषद के 120 सदस्यों के नामों की भी घोषणा की गई। घोषणा के बाद पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। पंकज चौधरी के नेतृत्व पर बीजेपी नेताओं ने अपना भरोसा जताया है। सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि यह बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच का फर्क है, जहां एक पार्टी कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है, जबकि अन्य पार्टियों में परिवार के सदस्य ही अध्यक्ष बनते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान ने कहा कि पंकज चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कुशलता से काम करेगी और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी, जिसका लक्ष्य जीत हासिल करना होगा। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि लंबे समय बाद नए अध्यक्ष चुने जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और इससे नई ऊर्जा आएगी। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकास का विजन नए अध्यक्ष के समर्थन और प्रयासों से जमीन पर उतरेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में राज्य में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।

रामलीला मैदान से राहुल गांधी की हुंकार, बीजेपी और ईसी को दी चेतावनी, आरएसएस पर भी साधा निशाना

राहुल बोले- मोदीजी का कॉन्फिडेंस खत्म- शाह के हाथ कांपते हैं, उनकी वोट चोरी पकड़ी गई; खड़गे बोले- हमारा वंदेमातरम् भी इन्होंने चोरी किया

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को कांग्रेस की वोट चोरी, गद्दी छोड़ो रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है और जल्द ही यह बात लोगों को भी पता चल जाएगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार संविधान में लिखा है, और इस पर हमला करना अंबेडकर जी का अपमान है।

राहुल गांधी ने आरएसएस को घेरा

राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी जी और हिंदू विचारधारा में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। लेकिन, उन्होंने मोहन भागवत के अंडमान में दिए एक बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था, विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। राहुल गांधी ने कहा, यह उनकी की विचारधारा है... मोहन भागवत कहते हैं- सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त इसी सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे सत्य के पीछे खड़े होकर पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे।

चुनाव आयोग पर सीधा निशाना

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान भाजपा ने 10,000 रुपये दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सच और झूठ की इस लड़ाई में चुनाव आयोग भाजपा सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को छूट देने के लिए नया कानून लाए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस कानून को बदल देगी और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने 2023 के चुनाव आयोग का हवाला देते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी आपसे (चुनाव आयुक्त) कह रही है, आप हिंदुस्तान के चुनाव आयुक्त हो, नरेंद्र मोदी के निर्वाचन आयुक्त नहीं हो। हम कानून पूर्वव्यापी रूप से बदलेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

वोट चोरी का आरोप, बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर तीखा जोरदार वार, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हल्लाबोल

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के मुद्दे पर अपना अभियान तेज करते हुए रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी महा रैली का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया।

संसद में जनता के मुद्दों पर चर्चा से इनकार करती है सरकार

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि जब संसद में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो मोदी सरकार ने बहस करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि हम पहले वंदे मातरम् पर चर्चा करेंगे, फिर वोट चोरी पर बात करेंगे। सदन में हम वंदे मातरम् पर चर्चा करते रहे, लेकिन मोदी सरकार में जनता के मुद्दों पर बात करने की हिम्मत नहीं दिखी।

बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर साधा निशाना

प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर दबाव की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया और बेबुनियाद आरोप लगाए गए। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा, जिन लोगों का दिल

कमजोर था... वो बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे-जैसे लोग बीजेपी में शामिल होते गए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ होते गए।

चुनाव आयोग पर भड़की प्रियंका

प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा, मैं चुनौती देती हूं- बीजेपी एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले। ये कभी नहीं जीत पाएंगे और ये बात बीजेपी भी जानती है। उन्होंने साफ कहा कि आज बीजेपी को चुनाव आयोग की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने चुनाव आयोग के तीन अधिकारियों, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, के नाम लेते हुए कहा कि यह देश इन तीन चुनाव आयुक्तों के नाम नहीं भूलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने लोकतंत्र पर वार किया है, और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर रहा है।

आवश्यक मुद्दों पर सरकार विफल

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर सदन में चर्चा न करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, जिसके तहत डॉलर का मूल्य 90 रुपए तक पहुंच गया है, देश की विदेश नीति फेल हो गई है, युवा पेपरलीक की समस्या से परेशान हैं, और सरकार देश की संपत्ति अडानी-अंबानी को सौंप रही है। इसके साथ ही, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दफ्तर में ही एक शख्स ने बेटिंग ऐप घोटाले किए हैं, लेकिन इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी संसद में बात नहीं होती।

बॉन्डी बीच पर गोलीबारी में 12 लोगों की दर्दनाक मौत, इलाके में दहशत

ऑस्ट्रेलिया।

सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर रविवार को दो बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें शुरुआती जानकारी के अनुसार 12 लोगों की मौत हो गई है। चश्मदीदों ने बताया कि हमलावरों ने 50 से अधिक गोलियां चलाईं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस भीषण घटना के वीडियो सामने आने के बाद, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने बयान जारी कर बॉन्डी बीच के दृश्यों को चौंकाने वाला और परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा, पुलिस और इमरजेंसी टीमें लोगों की जान बचाने के लिए मौके पर काम कर रही हैं। मेरी संवेदनाएं हर प्रभावित व्यक्ति के साथ हैं। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने पुलिस आयुक्त और न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर से बात की है और NSW पुलिस के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की। भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 2.17 बजे, न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक हो रही घटना पर कार्रवाई की पुष्टि की थी और लोगों को सुरक्षित जगह पर चले जाने की चेतावनी दी थी। बाद में, पुलिस ने बताया कि दोनों हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने लोगों से इलाके से दूर रहने और सभी पुलिस निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। यह गोलीबारी आठ दिन के यहूदी त्योहार हनुक्का की पहली रात को हुई।

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, हमलावरों ने शाम 6.30 बजे (ऑस्ट्रेलियाई समय) के ठीक बाद गोलीबारी शुरू की। उस समय सैकड़ों लोग इस यहूदी त्योहार की शुरुआत के मौके पर समुद्र किनारे एक कार्यक्रम के लिए बीच पर इकट्ठा हुए थे। कार्यक्रम में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि हमलावरों ने बच्चों और बुजुर्गों सहित लोगों को अंधाधुंध निशाना बनाया। सामने आए विजुअल्स में कुछ लोग जख्मी लोगों को सीपीआर देते हुए भी दिखाई दिए।

हेडगेवार पर महायुति में रार? स्मृति मंदिर स्मारक नहीं पहुंचे अजित पवार; बोले- हमारा फोकस राज्य के विकास के लिए

नागपुर। महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट आम बात है। खासकर तब जब राज्य में किसी भी प्रकार का चुनाव या फिर को राजनीतिक कार्यक्रम हो। तब यही सियासी गर्माहट अपने वास्तविक तपिश को छोड़कर सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। इसी क्रम में एक बार फिर बयानबाजी तब तेज हो गई जब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार रविवार को नागपुर में आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार के स्मारक नहीं पहुंचे। इस बात को आधार पर बनाकर चर्चा इस बात की भी तेज हो गई कि क्या हेडगेवार को लेकर महायुति गठबंधन के दलों में रार चल रहा है? हालांकि राजनीतिक गलियारों में बढ़ती चर्चा को देखते हुए एनसीपी ने अजित पवार के नागपुर नहीं जाने के पीछे का कारण साफ किया। पार्टी ने बयान जारी अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वह महायुति गठबंधन में राज्य के विकास के लिए शामिल हुई है, न कि किसी विचारधारा को अपनाने के लिए।

> हालांकि राजनीतिक गलियारों में बढ़ती चर्चा को देखते हुए एनसीपी ने अजित पवार के नागपुर नहीं जाने के पीछे का कारण साफ किया। पार्टी ने बयान जारी अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वह महायुति गठबंधन में राज्य के विकास के लिए शामिल हुई है, न कि किसी विचारधारा को अपनाने के लिए।

विचारधारा नहीं, विकास पर है फोकस- आनंद परांजपे

मामले में एनसीपी के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि पार्टी की विचारधारा सामाजिक सुधारकों शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले और डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहली बार नहीं है जब अजित पवार हेडगेवार स्मारक नहीं गए हैं। बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा व शिवसेना के कई विधायक आरएसएस के स्मृति मंदिर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हालांकि दूसरी ओर अजित पवार और एनसीपी के अन्य नेता इस कार्यक्रम से दूर रहे।

महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र

दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस समय नागपुर में चल रहा है। हर साल इस दौरान भाजपा के मंत्री और विधायक हेडगेवार और संघ के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर के स्मारक पर जाते हैं। पिछले साल एनसीपी की ओर से केवल दो विधायक ही वहां पहुंचे थे।

कांग्रेस ने भी एनसीपी पर साधा निशाना

गौरतलब है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी एनसीपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि अगर एनसीपी आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं है, तो सत्ता में बने रहना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाली सोच को बढ़ावा देता है। सचिन सावंत ने यह भी कहा कि आरएसएस को अब तक यह साफ करना चाहिए कि हिंदुत्व का असली मतलब क्या है। उन्होंने दावा किया कि संघ की बैठकों में बौद्धिक चर्चा से ज्यादा समाज को बांटने वाली बातें होती हैं।

देशभर में अगले हफ्ते से कड़ाके की सर्दी : उत्तराखंड-हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट

नई दिल्ली। अगले हफ्ते से देशभर में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। इस सर्दी का पहला बड़ा पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) 17 दिसंबर को हिमालयी राज्यों में पहुंचेगा। इसके असर से 18 से 20 दिसंबर के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। 21 और 22 दिसंबर को पहाड़ों से बादल हटते ही तापमान तेजी से गिरेगा। तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक नीचे जा सकता है। उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाएं यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य भारत तक पहुंचेंगी। इससे मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ जाएगी। इधर, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते सर्दी का असर कम हो गया है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में भी अगले 3 दिन तक शीतलहर का अलर्ट नहीं है। हालांकि, पारा लगातार लुढ़क रहा है। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा है। यहां शनिवार रात पारा 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर, हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने से ठंड बढ़ गई है। आज पहाड़ों पर बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे पारा 2-3°C और गिर सकता है। कश्मीर में 21 दिसंबर से 40 दिन तक चलने वाला सर्दियों का सबसे कड़ा दौर 'चिल्लई कलां' शुरू होगा। इस दौरान भीषण ठंड, बर्फबारी और पाला पड़ता है। पश्चिमी हिमालयी इलाकों में आखिरी बार 4 और 5 नवंबर को अच्छी बारिश और बर्फबारी हुई थी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन समारोह - सीएम योगी बोले- सरकार व संगठन मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे

लखनऊ। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के औपचारिक एलान के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया और कहा कि अब सरकार व संगठन मिलकर आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो प्रदेश की पहचान बदलनी शुरू हुई। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ जिससे निवेशकों ने प्रदेश की ओर देखना शुरू किया। हमें केंद्र से पूरा सहयोग मिलता रहा। हमने जब भी केंद्र से यूपी के विकास को लेकर कोई मांग की वो पूरी हुई। प्रदेश में पहली बार निवेशकों के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। विकास की इसी नीति और बदलाव के कारण यूपी बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आया और अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जबकि पहले यूपी की पहचान दंगों से होती थी। उन्होंने कहा कि आज यूपी की पहचान विकास और विरासत के साथ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

यूपी में सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर के लिए भूमि पूजन समारोह किया। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और अभी 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह कर राम मंदिर के पूर्ण होने की घोषणा की गई। यह भाजपा की सरकार में ही संभव हो सका है कि अब उत्तर प्रदेश की पहचान विकास, विरासत और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण होती है। आज सबसे ज्यादा हाईवे उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा मेट्रो रेल संचालित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पहले प्रदेश में तीन से चार घंटे ही बिजली आती थी पर अब यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश बन चुका है। यह सब डबल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हो सका है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस समय प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया की जा रही है। यह मतदाताओं को जोड़ने के लिए शुद्ध नीयत से किया जा रहा कार्य है।

हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम मतदाताओं के पास जाएं और उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने में मदद करें साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सूची में फर्जी मतदाता न जुड़ जाएं। ऐसे लोग भी हैं जो असम के हैं लेकिन मतदाता यूपी के हैं। हमारा उद्देश्य है कि फर्जी मतदाता न जुड़ पाएं और हमारे वोटर कम न होने पाएं। ये इसलिए जरूरी है कि जब साफ-सुथरी मतदाता सूची तैयार हो जाएगी तो कार्यकर्ताओं का तीन चौथाई काम पूरा हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में एक चौथाई काम करना होगा और भाजपा की तीन चौथाई सीटें सुनिश्चित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं है। महाराजगंज जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अगले एक महीने तक सिर्फ बूथ पर काम करने की जरूरत है।